मुख्यमंत्री ने जनपथ पर सड़क सुरक्षा की शपथ दिलाई

उन्होंने अमर जवान ज्योति पर सड़क दुर्घटनाओं में घायलों की जान बचाने वालों को सम्मानित किया

जयपुर, 13 दिसम्बर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शनिवार को जयपुर के जनपथ -स्थित अमर जवान ज्योति पर आयोजित सड़क सुरक्षा अभियान के राज्य स्तरीय समारोह में शिरकत की। उन्होंने इस दौरान सड़क सुरक्षा अभियान से संबंधित पोस्टर का विमोचन किया तथा उपस्थित लोगों को सड़क सुरक्षा की शपथ दिलाते हुए यातायात नियमों का पालन करने की अपील की।

■ **मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सड़क सुरक्षा जन-जागृति रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।**

मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में सड़क दुर्घटनाओं में घायलों की जान बचाने वाले नागरिकों को सम्मानित किया। शर्मा ने इन जीवन रक्षकों का हौसला बढ़ाते हुए उनके नेक कार्य की सराहना की। सम्मानित होने वालों में संदीप गुप्ता, नितेश यादव, सुनील सिरवी, संजय कुमार एवं सुरता देवी शामिल रहे। शर्मा ने कार्यक्रम में सड़क सुरक्षा जन-जागृति रथों को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने 500 ऑटो रिक्शों को भी फ्लैग ऑफ किया।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शनिवार को सड़क सुरक्षा अभियान के राज्य स्तरीय समारोह में शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने दिव्यांगजनों को हैलमेट वितरण किये।

ये सभी वाहन विभिन्न क्षेत्रों में जाकर आमजन को सड़क सुरक्षा के लिए जागरूक करेंगे। शर्मा ने इस अवसर पर दिव्यांगजनों को हैलमेट वितरण किया तथा व्यवसायिक वाहनों पर रिफ्लेक्टिव टेप लगाई।

मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में सड़क सुरक्षा का संदेश देने वाले गुब्बारे हवा में छोड़े। इस दौरान उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचन्द बैरवा, सांसद मंजू शर्मा, विधायक डॉ. गोपाल शर्मा, मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास सहित, विभिन्न विभागों के बड़े अफसर, बड़ी संख्या में स्कूल, कॉलेज के छात्र-छात्राएं एवं आमजन उपस्थित थे।

'बीमा क्षेत्र में 100 फीसदी एफडीआई स्वागत योग्य'

नयी दिल्ली, 13 दिसंबर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तथा पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने बीमा क्षेत्र में सौ फीसदी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई)

■ **कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदम्बरम ने मोदी सरकार के इस फैसले का स्वागत किया व कहा, भाजपा पहले इसका विरोध करती थी।**

की अनुमति देने के सरकार के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि यह अनुमति भाजपा के नेतृत्व वाली उसी सरकार ने दी है जो पहले एफडीआई का विरोध करती आ रही है।

चिदम्बरम ने शनिवार को सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में कहा "मैं बीमा क्षेत्र में 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति देने के सरकार के फैसले का स्वागत करता हूं। मुझे गुजराल सरकार का वह दिन याद है जब भाजपा ने संसद में उस विधेयक का विरोध किया था जिसमें बीमा क्षेत्र में 20 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति दी गई थी। यह एक लंबी दूरी है जिसे हमने 1997-98 से तय किया है।"

आज ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कहा कि शिवकुमार वर्तमान सत्र के समाप्त होते ही मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की जगह ले लेंगे।

स्टेट जीएसटी ने 200 करोड़ रुपये की कर चोरी पकड़ी

विभाग ने प्रदेश भर में 170 व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर एक साथ सर्वे कर यह उपलब्धि हासिल की

जयपुर, 13 दिसंबर। प्रदेश में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की कर चोरी के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस नीति तथा स्वच्छ कर प्रशासन की मंशा के अनुरूप, राज्य के वाणिज्य कर विभाग (स्टेट जीएसटी) द्वारा बड़ी कार्यवाही की गई है। विभाग ने प्रदेशभर में एक साथ 110 व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर सर्वे कार्यवाही करते हुए लगभग 200 करोड़ रुपये की कर चोरी का खुलासा किया है।

■ **विभाग को लम्बे समय से प्रदेश में प्लाईवुड, सैनेटरी आइटम, लोहा स्क्रैप, टाइल्स, खाद्य तेल, होटल, कपास, टिम्बर व रियल एस्टेट आदि सैक्टर्स में कर चोरी की सूचनायें प्राप्त हो रही थीं।**

यह कार्यवाही विभाग के मुख्य आयुक्त कुमार पाल गौतम के निर्देश पर की गई। अभियान को सफलतापूर्वक अंजाम देने के लिए वाणिज्य कर विभाग के 300 से अधिक अधिकारियों को शामिल करते हुए अलग-अलग टीमें गठित की गईं, जिन्होंने प्रदेश के विभिन्न जिलों में एक साथ यह कार्यवाही की।

विभाग को लंबे समय से सूचनाएं प्राप्त हो रही थीं कि प्रदेश में प्लाईवुड, सैनेटरी आइटम, लोहा स्क्रैप, टाइल्स, खाद्य तेल, होटल, कपास, टिम्बर, रियल एस्टेट सहित, कई सेक्टर्स में कुछ व्यापारी कर चोरी में संलिप्त हैं। इन्हीं सूचनाओं के आधार पर यह व्यापक अभियान चलाया गया।

प्रदेश में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर विभिन्न सेक्टर्स में एक साथ कार्यवाही की गई है, जिससे कर चोरी में लिप्त व्यापारियों में हड़कंप मच गया। कार्यवाही के दौरान, कई स्थानों से कच्ची पर्चियां, फर्जी बिलिंग एवं अन्य आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए गए हैं। सर्वे कार्यवाही के दौरान ही कई व्यापारियों ने कर चोरी स्वीकार करते हुए स्वेच्छा से लगभग 10 करोड़ रुपये की राशि विभाग में जमा करवाई है। विभाग द्वारा जब्त दस्तावेजों के आधार पर अब विस्तृत जांच की जाएगी, जिससे आगे और भी बड़ी राशि राजस्व के रूप में प्राप्त होने की संभावना है।

उल्लेखनीय है कि वाणिज्य कर विभाग द्वारा वर्तमान में कर चोरी के विरुद्ध सघन अभियान चलाया जा रहा है और आने वाले दिनों में इस प्रकार की कार्यवाहियों में और अधिक तेजी लाई जाएगी।

'मोटी तन्ख्वाह के ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

सुरक्षा से संबंधित होता है और इसे श्रम कानून के तहत प्रबंधकीय पर्यवेक्षण से नहीं जोड़ा जा सकता। कोर्ट ने यह भी जोर दिया कि एक नियामक ढांचे में प्रयुक्त कानूनी शब्दों को दूसरे नियामक ढांचे में स्वचालित रूप से लागू नहीं किया जा सकता, जिनका उद्देश्य और संदर्भ अलग होता है।

बकाया वेतन के मामले में, कोर्ट ने औद्योगिक ट्रिब्यूनल के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि पायलटों की बर्खास्तगी अवैध थी और बिना उचित प्रक्रिया के की गई थी।

सुप्रीम कोर्ट के पिछले फैसलों को लागू करते हुए, खंडपीठ ने यह दोहराया कि गलत बर्खास्तगी के मामलों में सेवा की निरंतरता और बकाया वेतन के साथ पुनर्नियुक्ति सामान्य नियम है, विशेष रूप से जब नियोक्ता यह साबित करने में असमर्थ हो कि कर्मचारी अन्यत्र लाभकारी रूप से कार्यरत था।

संसद पर आतंकी हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि

नयी दिल्ली, 13 दिसंबर। संसद पर वर्ष 2001 में आज ही के दिन किये गये आतंकवादी हमले की 24 वीं बरसी पर शनिवार को यहां देश के शीर्ष नेतृत्व ने इस हमले का मुकाबला करते हुए प्राण न्योच्छावर करने वाले सुरक्षाकर्मियों को श्रद्धापूर्वक नमन किया और आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता का संकल्प लिया।

उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभा के सभापति सी. पी. राधाकृष्णन, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने संसद भवन परिसर में शहीदों को नमन किया। इस अवसर पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, अनेक केन्द्रीय मंत्री, सांसद, पूर्व सांसद और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

राधाकृष्णन ने अपने संदेश में कहा, "मैं देश के साथ मिलकर उन बहादुर सुरक्षाकर्मियों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ, जिन्होंने हमारी संसद की पवित्रता की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी। उनका अटूट साहस और सर्वोच्च बलिदान आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर खड़े रहने के हमारे राष्ट्र के संकल्प की एक स्थायी याद दिलाता है।"

मोदी ने शहीद सुरक्षा कर्मियों के शौर्य को स्मरण करते हुए कहा, "आज के दिन हमारा देश 2001 में संसद पर हुए जघन्य हमले में अपने प्राण न्योछावर करने वाले वीरों को याद करता है।

कांग्रेस की "वोट चोर गद्दी छोड़" महारैली आज

दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित महारैली के आयोजन की सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं

नयी दिल्ली, 13 दिसंबर। कांग्रेस ने वोट चोरी के खिलाफ चलाए गये अपने अभियान के तहत रविवार 14 अप्रैल को यहां रामलीला मैदान में होने वाली "वोट चोर-गद्दी छोड़" महा रैली की तैयारी पूरी कर ली है।

■ **दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेन्द्र यादव ने एक वीडियो जारी कर रैली के आयोजन की तैयारियों की जानकारी दी व लोगों से इसमें शामिल होने की अपील की।**

दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने शनिवार को एक वीडियो जारी कर बताया कि रैली की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं।

यादव ने रैली स्थल रामलीला मैदान से जारी संदेश में लोगों से बड़ी संख्या में इस रैली में शामिल होने का आग्रह करते हुए कहा "मेरी अपील है कि इस रैली में शामिल होकर वोट चोरी के खिलाफ आवाज को बुलंद कीजिए और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे तथा पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के हाथों को मजबूत करिए।"

इससे पहले कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा "जब वोट चोरी पकड़ी गई तो चोर बौखला गया और अब वो मुद्दों को भटकाने का काम कर रहा है। वोट चोरी से जुड़े हमारे सवाल स्पष्ट हैं, जिन्हें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी लगातार पूछ रहे हैं, लेकिन जवाब नहीं मिल रहा है।

अब 14 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में वोट चोरी के खिलाफ एक विशाल रैली हो रही है। मेरी अपील है कि आप सब भी रैली में आइए, क्योंकि हमें वोट चोरों को भागने नहीं देना है।"

जस्टिस ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

यह मामला न्यायमूर्ति प्रतिभा एम.सिंह और शैल जैन की खंडपीठ समक्ष सूचीबद्ध किया गया था, लेकिन न्यायमूर्ति शैल जैन ने इस मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया, क्योंकि उनका बेटा इंडिगो में पायलट है।

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, इस प्रकरण को "किसी ऐसी खंडपीठ के समक्ष सूचीबद्ध करें, जिसमें हममें से एक (न्यायमूर्ति शैल जैन) सदस्य न हों, मुख्य न्यायाधीश के आदेशों के अधीना।"

अब यह प्रकरण किसी अन्य खंडपीठ के समक्ष सम्भवतः 19 दिसम्बर को आएगा।

इंडिगो के वकील वी. लक्ष्मीकुमारन ने कहा कि एयरलाइन ने बिना किसी विवाद के बेसिक कस्टम ड्यूटी का भुगतान किया था, जब उसके विमान के इंजन और पार्ट्स मरम्मत के बाद पुनः आयात किए गए थे।

दिल्ली में वायु प्रदूषण में भारी तेजी

ग्रैप-3 नियम लागू करने के कुछ ही घंटों में ग्रैप-4 नियम लागू किए गए

नयी दिल्ली, 13 दिसंबर। दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण तेजी से बढ़ ने के कारण वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने शनिवार को सुबह ग्रैप-3 लागू किया और शाम होते-होते ग्रैप-4 लागू करने की स्थिति बन गयी। ग्रैप, यानी चरणबद्ध प्रतिक्रिया कार्य योजना के चार चरण हैं जिनके तहत प्रदूषण कम करने के लिए जरूरी अलग-अलग उपायों को लागू किया जाता है। इसे लागू करने की जिम्मेदारी वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की है।

■ **वायु प्रदूषण प्रबंधन आयोग ने कहा, एयर क्वालिटी इंडैक्स अति गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है तुरंत सुधार होने की संभावना नहीं है।**

दिल्ली-एनसीआर में शुक्रवार तक ग्रैप-2 लागू था। आयोग ने शनिवार सुबह ग्रैप-3 लागू करने का फैसला किया जिसमें और कड़े प्रतिबंधों तथा अधिक उपायों का प्रावधान है। हालांकि इसके कुछ ही घंटे बाद तेजी से बढ़ ते प्रदूषण का हवाला देते हुए ग्रैप-4 लागू कर दिया गया।

आयोग ने शनिवार शाम जारी एक बयान में कहा कि शहर में हवा की गुणवत्ता लगातार खराब हो रही है। दिल्ली में शाम चार बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 431 दर्ज किया गया, जो धीमी हवा की गति, स्थिर वातावरण, खराब मौसम की स्थिति और प्रदूषकों के खराब फैलाव के कारण शाम छह बजे तक बढ़ कर 441 हो गया।

बयान में कहा गया है, "एक्यूआई अति-गंभीर श्रेणी के करीब पहुंचने और मौसम की स्थिति में तुरंत कोई सुधार की संभावना न होने के कारण ग्रैप-4 के तहत सभी उपायों को तुरंत प्रभाव से लागू करने का फैसला किया गया है।"

ग्रैप-4 के उपाय तब लागू किये जाते हैं जब एक्यूआई 450 से ऊपर चला जाता है या उसके ऊपर जाने का अनुमान होता है। इसमें स्थानीय प्रशासन के फैसलों के आधार पर निर्माण गतिविधियों पर रोक, कुछ पुराने मानकों के वाहनों के प्रवेश पर रोक और स्कूलों को बंद करने जैसे सबसे सख्त प्रतिबंध शामिल हैं।

हिट एण्ड एन केस, आरोपी मिहिर शाह की जमानत याचिका खारिज

नई दिल्ली, 13 दिसंबर। सुप्रीम कोर्ट ने 2024 के मुंबई बीएमडब्ल्यू हिट-एंड-रन मामले में आरोपी मिहिर शाह की जमानत याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। मिहिर शाह शिवसेना के पूर्व नेता का बेटा है। शीर्ष कोर्ट ने टिप्पणी की कि इन लड़कों को सबक सिखाने की जरूरत है। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एजी मसीह की बेंच ने इस तथ्य पर गौर किया कि आरोपी एक संपन्न परिवार से है और उसके पिता उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना से जुड़े रहे हैं। बेंच ने शुक्रवार को कहा, वह शेड में मर्सिडीज खड़ी करता है, बीएमडब्ल्यू निकालता है, उससे टक्कर मारता है और फरार हो जाता है।

'मोदी सरकार नाम बदलने में धुरंधर है'

नयी दिल्ली, 13 दिसंबर। कांग्रेस ने सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना-मनरेगा का नाम बदलने पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए शनिवार को कहा कि पूरे देश को मालूम है कि नाम बदलने में मोदी सरकार धुरंधर है लेकिन अब यह भी साफ हो गया है कि उसे सिर्फ पंडित जवाहर लाल नेहरू से ही नहीं, बल्कि महात्मा गांधी नाम से भी नफरत है।

■ **मनरेगा का नाम बदलने पर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर तंज कसा।**

कांग्रेस ने कहा कि महात्मा गांधी के नाम पर मनरेगा योजना चल रही थी और लंबे समय से इस योजना के तहत गांवों में लोगों को रोजगार मिल रहा है लेकिन अब गांधी शब्द हटाकर सरकार ने योजना का नाम बापू कर दिया है जिससे स्पष्ट हो गया है कि सरकार को गांधी नाम से भी नफरत है।

पार्टी संचार विभाग के प्रभारी जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में मनरेगा का नाम बदलने के निर्णय पर कहा, "योजनाओं के नाम, कानून के नाम बदलने में मोदी सरकार धुरंधर है, इसका कोई मुकाबला नहीं है। निर्मल भारत अभियान को स्वच्छ भारत अभियान बनाया, ग्रामीण एलपीजी वितरण कार्यक्रम को उज्ज्वला नाम दिया... पैकेजिंग, ब्रांडिंग और नाम देने में ये धुरंधर है।"

उन्होंने कहा "हैरानी इस बात की है कि पंडित नेहरू से तो इन्हें नफरत है लेकिन महात्मा गांधी से इतनी नफरत, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना 2005 से चल रही है... इसका नाम आप पूज्य बापू रोजगार गारंटी योजना कर रहे हैं, महात्मा गांधी नाम से क्या दिक्कत है..."

पंकज ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

पीयूष गोयल रविवार को लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में नए अध्यक्ष के नाम की घोषणा करेंगे।

भारत पर लगे टैरिफ के खिलाफ अमेरिकी कांग्रेस में प्रस्ताव पेश

वाशिंगटन, 13 दिसंबर। अमेरिका में कांग्रेस (संसद) के निचले सदन प्रतिनिधि सभा के तीन सदस्यों ने राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप की ओर से भारत से सामानों के आयात पर लगाये गये 50 प्रतिशत तक शुल्क को समाप्त करने के लिए प्रस्ताव पेश किया है।

■ **तीन सदस्यों ने कांग्रेस के निचले सदन, "हाउस ऑफ रैप्रैजेंटेटिव" में प्रस्ताव पेश किया**

■ **प्रस्ताव डेबोरा रॉस, मार्क वेसी व राजा कृष्णमूर्ति ने पेश किया और ट्रंप द्वारा भारत पर लगाए गए 50 प्रतिशत टैरिफ को अमेरिका के लिए नुकसानदेह बताया।**

अमेरिकी सांसदों ने शुक्रवार को पेश किये गये इस प्रस्ताव में इन शुल्कों को अवैध बताया और कहा है कि इससे अमेरिकी श्रमिकों और उपभोक्ताओं को नुकसान पहुंचेगा। साथ ही अमेरिका-भारत संबंधों में भी तनाव पैदा होगा। यह प्रस्ताव रैप्रेज़ेंटेटिव डेबोरा रॉस, मार्क वेसी और राजा कृष्णमूर्ति ने पेश किया।

रॉस ने कहा, "उत्तर कैरोलिना की अर्थव्यवस्था व्यापार, निवेश और एक जीवंत भारतीय अमेरिकी समुदाय के ज़रिए भारत से गहराई से जुड़ी हुई है।" उन्होंने बताया कि भारतीय कंपनियों ने राज्य में 100 करोड़ अमेरिकी डॉलर से ज़्यादा का निवेश किया है, जिससे जीवन विज्ञान और प्रौद्योगिकी जैसे सेक्टर्स में हज़ारों नौकरियाँ पैदा हुई हैं, जबकि उत्तर कैरोलिना के कारोबारी हर साल भारत को हजारों डॉलर का सामान मुहैया कराते हैं।

वेसी ने कहा, "भारत एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक, आर्थिक और रणनीतिक साझेदार है और ये अवैध टैरिफ उत्तरी टेक्सास के लोगों पर एक रोज़मर्रा का कर हैं जो पहले से ही बढ़ती कीमतों से जूझ रहे हैं।"

भारतीय-अमेरिकी कांग्रेसी राजा कृष्णमूर्ति ने टैरिफ को नुकसानदायक बताते हुए कहा कि वे आपूर्ति श्रृंखला को बाधित करते हैं, अमेरिकी श्रमिकों को नुकसान पहुँचाते हैं, और उपभोक्ताओं के लिए लागत बढ़ ाते हैं। उन्होंने कहा कि शुल्क खत्म करने से अमेरिका-भारत आर्थिक और सुरक्षा सहयोग मज़बूत होगा।

यह प्रस्ताव कांग्रेसी डेमोक्रेट्स द्वारा ट्रंप के एकतरफा व्यापारिक कार्यों को चुनौती देने और भारत के साथ तनावपूर्ण संबंधों को फिर से ठीक करने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है। अक्टूबर की शुरुआत में रॉस, वेसी और कृष्णमूर्ति ने कांग्रेसी रो खन्ना और 19 अन्य सांसदों के साथ मिलकर राष्ट्रपति से टैरिफ नीति को पलटने और द्विपक्षीय संबंधों को सुधारने का आग्रह किया था।

पार्टीशन के आठ दशक ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

चुनौती देती है। यह परोक्ष रूप से एक असहज ऐतिहासिक सच्चाई को स्वीकार करती है कि संस्कृत की दुनिया उन इलाकों तक फैली हुई थी, जो आज पाकिस्तान के भीतर आते हैं, और जिनका बौद्धिक व सांस्कृतिक संबंध कश्मीर से रहा है। सीमाओं के बनने से बहुत पहले, संस्कृत के शास्त्रीय ग्रंथ-दर्शन, महाकाव्य और टीकाएँ-इसी भूभाग में लिखे, पढ़े और आगे बढ़ाए गए। कश्मीर स्वयं संस्कृत अध्ययन का एक बड़ा केन्द्र था, जहाँ से कश्मीर शैव दर्शन जैसी प्रभावशाली परंपराएँ निकलीं, जिन्होंने घाटी से बहुत दूर भारतीय दर्शन को आकार दिया।

■ **क्या इसका यह अर्थ लगाया जा सकता है कि दक्षिण एशिया में शांति ज़मीन की मिल्कियत के बारे में समझौतों से नहीं, बल्कि उस साहस को स्वीकार करने से आएगी कि दोनों देशों की ऐतिहासिक धरोहर व पृष्ठभूमि में काफी समानताएं हैं, काफी "ओवर लैपिंग" है।**

संस्कृत को अपनी ही विद्वत परंपरा के हिस्से के रूप में अपनाकर पाकिस्तान इस धारणा को कमजोर करता है कि सभ्यतागत इतिहास को मौजूदा राजनीतिक सीमाओं और दावों का साफ-साफ आईना होना चाहिए। इससे न तो पाकिस्तान का कश्मीर पर आधिकारिक रुख बदलता है और न ही भारत के क्षेत्रीय दावों को वैधता मिलती है। लेकिन यह कश्मीर को एक हथियारबंद एकल पहचान के बजाय, सदियों में बनी कई परतों वाली सभ्यता के रूप में देखने की बौद्धिक गुंजाइश ज़रूर खोलता है।

यह अंतर शांति के लिए मायने रखता है। कश्मीर आंशिक रूप से इसलिए भी अनसुलझा रहा है, क्योंकि वह दोनों पक्षों के लिए पहचान का प्रतीक बन चुका है, जहाँ बारीकियों या साझा स्मृतियों के लिए बहुत कम जगह बचती है। सांस्कृतिक कट्टरता राजनीतिक रुख को और कठोर बना देती है। इसके विपरीत, अकादमिक जुड़ाव जटिलता और ऐतिहासिक गहराई लाता है, वही तत्व, जो सुलह के लिए जरूरी है, लेकिन जिन्हें राजनीति अक्सर दबा देती है।

इसका एक शांत मानवीय पक्ष भी है। जब पाकिस्तानी विद्वान कश्मीर के बौद्धिक इतिहास से जुड़े संस्कृत ग्रंथों का गंभीर अध्ययन करते हैं, तो कश्मीर केवल नक्शे की समस्या नहीं रह जाता, बल्कि एक जीती-जागती, विवादित विरासत के रूप में सामने आता है। यह भारतीय पाठकों को भी चुनौती देता है कि वे ऐसे प्रयासों को खतरे या समझौते के रूप में नहीं, बल्कि साझा सभ्यतागत स्वामित्व के दावे के रूप में देखें।

ऐसे समय में जब कश्मीर पर औपचारिक बातचीत रूकी हुई है और भरोसा बढ़ाने के उपाय लगभग नहीं के बराबर हैं, इस तरह की पहलें इसलिए महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये राज्य की औपचारिक राजनीति से नीचे के स्तर पर काम करती हैं। ये न तो सीमाएँ बदलती हैं और न ही विवाद सुलझाती हैं, लेकिन वे उस सभ्यतागत कठोरता को ढीला करती हैं, जो इन विवादों को स्थायी रूप से जमाए रखती हैं।

इस मायने में, लाहौर की संस्कृत की क्लास सिर्फ़ अतीत से जुड़ी बात नहीं है। यह एक गहरी आधुनिक धारणा पर सवाल उठाती है कि इतिहास भी, ज़मीन की तरह, विशेष रूप से एक ही कहानी का होना चाहिए।

एक साझा बौद्धिक विरासत को फिर से खोलकर, संस्कृत के साथ पाकिस्तान का यह जुड़ाव एक मामूली, लेकिन शक्तिशाली याद दिलाता है कि दक्षिण एशिया में शांति की शुरुआत शायद ज़मीन के समझौतों से नहीं, बल्कि एक-दूसरे के मिले-जुले इतिहास को स्वीकार करने के साहस से हो सकती है।

'ग्राम ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

बताया कि पंचायती राज विभाग ने गत 10 जनवरी को पंचायती राज अधिनियम की धारा 101 के तहत पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्सीमांकन, नवसृजन और पुनर्गठन के लिए जिला कलेक्टर से प्रस्ताव मांगे थे। राज्य सरकार ने धौलपुर व करौली जिला कलेक्टर की ओर से भेजे गये प्रस्तावों को नहीं मानते हुए, गत 20 नवंबर को मनमाने तरीके से संबंधित ग्राम पंचायतों के मुख्यालय बदल दिए। इसके अलावा, करौली जिले से जुड़े मामले में पंचायत मुख्यालय करीब 14 किलोमीटर दूर कर दिया, जबकि नियमानुसार यह दूरी अधिकतम पांच किलोमीटर से अधिक नहीं हो सकती। याचिकाओं में कहा गया कि इन ग्राम पंचायत मुख्यालयों में पहले से ही राज्य सरकार से सभी कार्यालय मौजूद हैं। इसके बावजूद सरकार ने मनमाने तरीके से अधिसूचना जारी कर इनके मुख्यालय बदल दिए। उक्त मामलों पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है।

मनरेगा हुआ खत्म, उसकी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

वर्ष 2022 से ही मनरेगा केन्द्र और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच टकराव का कारण बन गया था, जब केन्द्र सरकार ने योजना के कार्यान्वयन में कथित वित्तीय गड़बड़ियों का हवाला देते हुए राज्य को दी जाने वाली मनरेगा धनराशि रोक दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में केन्द्र को इस योजना को फिर से शुरू करने का आदेश दिया, लेकिन इससे स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ, क्योंकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को केन्द्र के दिशा-निर्देशों के पेपर को फाड़ते हुए देखा गया था। मनरेगा को बदलते हुए, केन्द्र सरकार विपक्ष द्वारा आरोपित यह छवि मिटाना चाहती है कि केन्द्र विपक्ष शासित राज्यों को केन्द्रीय निधियों से वंचित कर रहा है। अभी तक, कांग्रेस मनरेगा योजना का श्रेय लेती रही है, तृणमूल कांग्रेस जैसी क्षेत्रीय और गैर-एनडीए पार्टियाँ केन्द्र सरकार पर राज्य को मनरेगा फंड से वंचित करने का आरोप लगाती रही हैं। इस एक्ट का नाम बदलकर और इसके दायरे को बढ़ाकर, एनडीए सरकार यह दावा कर सकती है कि उसने ग्रामीण रोजगार सृजन में यूपीए के मुकाबले अधिक काम किया है। अधिकारियों ने कहा, नए प्रस्तावित कानून की विशेषताएँ अभी स्पष्ट नहीं हैं, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह योजना विकसित भारत इंफ्रास्ट्रक्चर विकास योजना के तहत आएगी। पीबीजीआरजी के तहत प्राथमिकता जल सुरक्षा को दी जाएगी और काम विकसित ग्राम पंचायत योजनाओं के तहत किया जाएगा, ताकि खेती के मौसम के दौरान श्रमिकों की कोई कमी न हो।

अपने गढ़ में ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

छोड़ दी, तो इससे पहले थरूर सोनिया गांधी की अध्यक्षता में हुई उस बैठक से भी नदारद रहे, जहां पार्टी की शीतकालीन सत्र की रणनीति पर चर्चा होनी थी। वहीं अब अपने लोकसभा क्षेत्र तिरुवनंतपुरम में स्थानीय निकाय चुनावों में भाजपा की जीत पर विरोधी दल को थरूर द्वारा बधाई देना भी चर्चा का विषय बन चुका है।

केरल स्थानीय निकाय चुनाव के परिणामों के बीच कांग्रेस नेता शशि थरूर का संसदीय क्षेत्र तिरुवनंतपुरम चर्चा का विषय बना गया है। कारण है, थरूर के संसदीय क्षेत्र में भाजपा की बढ़त, जिससे कांग्रेस के लिए मुकाबला काफी चुनौतीपूर्ण बन गया है। ताजा अपडेट के अनुसार तिरुवनंतपुरम नगर निगम के 101 वार्डों के आए नतीजों में भाजपा समर्थित एनडीए ने 50 सीटों पर कब्जा जमाया है।

तिरुवनंतपुरम नगर निगम में भाजपा-एनडीए को मिले जनादेश पर पीएम मोदी ने खुशी जताई है। अपने एक्स पोस्ट में उन्होंने इसे केरल की राजनीति का निर्णायक मोड़ बताया।

राष्ट्रदूत (एच.यू.एफ.) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, सुधर्मा, एम.आई.रोड़, जयपुर एवं सुधर्मा-II, लालकोठी शॉपिंग सेंटर, टोंक रोड़, जयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादकः- राजेश शर्मा। आर.एन.आई. नं. 3641/57, ई-मेल-rastrdut@gmail.com कोटा कार्यालयः-पलायथा हाउस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन:2386031, 2386032, फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालयः-कुंम्भाना हाउस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन:2200660, फैक्सः 0151-2527371 उदयपुर कार्यालयः-आयड, मेन रोड आयड, उदयपुर। फोनः 2413092, 2418945, फैक्सः 0294-2410146 अजमेर कार्यालयः-घूघरा घाटी, जयपुर रोड,अजमेर। फोनः 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोनः 226422, 226423, फैक्सः 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोनः 230200, 230400, फैक्सः 07469-230600 चूरू कार्यालयः एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोनः 256906, 256907, फैक्स:01562-256908